IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)
e-ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 18, Issue 1 .Ver. IV (Jan. 2016), PP 68-71
www.iosrjournals.org

स्मार्ट सिटी परियोजना :: वर्त्तमान परिदृश्य और उभरती चुनौतियाँ

डॉ0 मु0 शमीम
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य , रा0 महा0 महराजगंज यू0 पी0

विकसित अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, ''मिसाइल मैन'' एवं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा था, उस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्मार्ट सिटी परियोजना उनके सपने को साकार करने का रूप ले रहा है। भारत सरकार ने शहरी भारत को रहन–सहन, परिवहन और अन्य अत्याधुनिक सुबिधाओं से लैस करने के इरादे से तीन महत्वाकांक्षी योजनाओं–स्मार्ट सिटीज, अटल मिशन फार रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (अमृत) और सभी आवास–योजना का शुभारम्भ किया है।

परिचय

भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31: को शहरों में बसता है और इनका सकल घरेलू उत्पाद में 63: (जनगणना 2011) का योगदान हैं। ऐसी उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40: रहेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 75: का होगा । इसके लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है। ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं लोगों और निवेश को आकर्षित करने, विकास एवं प्रगति के एक गुणी चक्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण हैं। स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में एक कदम है।

स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा एक अभिनव और नई पहल है।

स्मार्ट सिटी उनकी सबसे अहम जरूरतों एवं जीवन में सुधार करने के लिए सबसे बड़े अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। बदलाव के लिए दृष्टिकोण की श्रृंखला अपनाई जाती है – डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी योजनाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, और नीति में बदलाव। हमेशा लोगों को प्राथमकिता दी जाती है।

स्मार्ट सिटी मिशन के दृष्टिकोण में, उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देने का है जो मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएँ और अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करे, एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण एवं 'स्मार्ट' समाधानों के प्रयोग का मौका दें। विशेष ध्यान टिकाऊ और समावेशी विकास पर है और एक रेप्लिकेबल मॉडल बनाने के लिए है जो ऐसे अन्य इच्छुक शहरों के लिए प्रकाश पुंज का काम करेगा। स्मार्ट सिटी मिशन ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए है जिसे स्मार्ट सिटी के भीतर और बाहर दोहराया जा सके, विभिन्न क्षेत्रों और देश के हिस्सों में भी इसी तरह के स्मार्ट सिटी के सृजन को उत्प्रेरित किया जा सके।

स्मार्ट सिटी मिशन रणनीति

- पूरे शहर के लिए पहल जिसमे कम से कम एक स्मार्ट समाधान शहरभर में लागू किया गया है
- क्षेत्र का कदम–दर–कदम विकास – क्षेत्र के आधार पर प्रगति के तीन मॉडल
- रेट्रोफिटिंग
- पुनर्विकास
- हरितक्षेत्र
- कोर बुनियादी सुविधाओं के तत्वकोर बुनियादी सुविधाओं के तत्व
- पर्याप्त पानी की आपूर्ति
- निश्चित विद्युत आपूर्ति
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता
- कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन
- किफायती आवास, विशेष रूप से गरीबों के लिए
- सुदृढ़ आई टी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण
- सुशासन, विशेष रूप से ई–गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी
- टिकाऊ पर्यावरण
- नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों एवं बुजुर्गों की सुरक्षा, और

- स्वास्थ्य और शिक्षा

कवरेज और अवधि

इस मिशन में 100 शहरों को शामिल किया जाएगा और इसकी अवधि पांच साल (वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2019–20) की होगी। मिशन उसके बाद शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किए जाने एवं प्राप्त सीखों को शामिल किये जाने के साथ जारी रखा जा सकता है।

100 स्मार्ट शहरों की कुल संख्या एक समान मापदंड के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वितरित किया गया है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र की शहरी जनसंख्या और राज्य संघ राज्य क्षेत्र में वैधानिक शहरों की संख्या को बराबर वजन (50:50) देता है। इस फार्मूले के आधार पर, प्रत्येक राज्य केन्द्र शासित प्रदेशों में कम से कम एक होने के साथ, संभावित स्मार्ट शहरों की एक निश्चित संख्या होगी। प्रत्येक राज्य केन्द्र शासित प्रदेशों से संभावित स्मार्ट शहरों की संख्या इंगित संख्या पर सीमित की जाएगी। इस वितरण फार्मूला का इस्तेमाल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन– अमृत के तहत धनराशि के आवंटन के लिए भी किया गया है।

स्मार्ट सिटी के वितरण की समीक्षा मिशन के कार्यान्वयन के दो साल बाद की जाएगी। चुनौती में राज्यों ६ शहरी स्थानीय निकायों के प्रदर्शन के आकलन के आधार पर राज्यों के बीच शेष संभावित स्मार्ट शहरों में से कुछ का पुनःआवंटन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है।

स्मार्ट सिटी का वित्त पोषण

स्मार्ट सिटी मिशन एक केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के रूप में संचालित किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा मिशन को पांच साल में 48,000 करोड़ रुपये, करीब प्रति वर्ष प्रति शहर 100 करोड़ रुपये औसत वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। एक समान राशि, एक मेल के आधार पर, राज्य ६ यूएलबी द्वारा योगदान किया जाएगाय इसलिए, सरकार ६ यूएलबी धन का लगभग एक लाख करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के विकास के लिए उपलब्ध होगा।

अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरणसरकारी योजनाओं

व्यापक विकास क्षेत्रों में भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को एकीकृत करके होता है। सरकार की कई क्षेत्रीय योजनाएँ इस लक्ष्य में एकाग्र होती हैं हालांकि उनके रास्ते अलग है । शहरी परिवर्तन को प्राप्त करने में अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के बीच एक मजबूत पूरक है। अमृत एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जबकि स्मार्ट सिटी मिशन एक क्षेत्र आधारित रणनीति है। इसी तरह, केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यक्रमों ६ स्मार्ट शहरों के मिशन के साथ योजनाओं के अभिसरण की मांग करके काफी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। योजना बनाने के स्तर पर ही, शहरों को एससीपी में अमृत के साथ स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम), राष्ट्रीय विरासत शहर का विकास और संवर्धन योजना (ह्रदय)– बाहरी वेबसाइट जो एक नई विंडो में खुलती है, डिजिटल भारत कौशल विकास, सभी के लिए आवास, संग्रहालय के निर्माण के लिए संस्कृति विभाग द्वारा वित्त पोषित और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संस्कृति के रूप में सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़े अन्य कार्यक्रम में अभिसरण की तलाश करना चाहिए।

यह पहली बार है जब एक एमओयूडी कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए शहरों का चयन करने के लिए 'चौलेंज' या प्रतियोगिता विधि का उपयोग और क्षेत्र के आधार पर विकास की एक रणनीति का प्रयोग किया गया है। यह 'प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद' की भावना को दर्शाता है। राज्य और शहरी स्थानीय निकायों को स्मार्ट सिटी के विकास में एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभानी होगी। इस स्तर पर स्मार्ट नेतृत्व और दृष्टि एवं निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता मिशन की सफलता का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण कारक होगी।

नीति निर्माताओं, कार्यान्वयन करने वालों एवं अन्य हितधारकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर रेट्रोफिटिंग की अवधारणाओं को समझना, पुनर्विकास और ग्रीनफील्ड विकास हेतु क्षमता सहायता की जरूरत होगी। चौलेंज में भाग लेने से पूर्व योजना बनाने के दौर में ही समय और संसाधनों में प्रमुख निवेश करना होगा। यह पारंपरिक डीपीआर संचालित दृष्टिकोण से अलग है। स्मार्ट सिटी मिशन को सक्रिय रूप से प्रशासन और सुधारों में भाग लेने वाले स्मार्ट लोगों की आवश्यकता है। नागरिक भागीदारी शासन में एक औपचारिक भागीदारी की तुलना में काफी अधिक है। स्मार्ट लोगों की भागीदारी आईसीटी के बढ़ते उपयोग, विशेष रूप से मोबाइल आधारित उपकरणों के माध्यम से स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) द्वारा सक्रिय किया जायेगा।

कार्यवृत्त

इन परियोजनाओं से देशवासियों की उम्मीदों को नई उड़ाने मिलती नजर आ रही है, और उनके सपनों कां पंख। स्मार्ट सिटी परियोजना उस कल्पना को साकार करने वाली है, जिसमें शहर की सड़कों पर स्थित हर खम्भे पर कैमरे लगे हों, रात में पैदल यात्री के उपस्थित होने पर बल्ब स्वतः जल जाए अन्यथा डिम हो जाये, सूर्य की रोशनी के अनुरूप घरों की लाइटें घटाई–बढ़ाई जा सके और शिक्षक की गैर–हाजरी पर किसी स्कूल का शिक्षक वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए पढ़ा सके। ऐसी महत्त्वाकांक्षी स्वर्णिम योजना के साकार होने पर निः सन्देह भारत, विश्व पटल पर एक मजबूत देश के रूप में स्थापित होगा।

स्मार्ट सिटी मिशनः–स्मार्ट सिटी का मकसद है नागरिकों का उच्चीकृत सेवा एवं सुविधा प्रदान करना। स्मार्ट–सिटी, मिशन के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबन्धन सरकार द्वारा २२ जून २०१५ को प्रारम्भ किया गया है।

स्मार्ट सिटी को किसी दायरे में रखकर परिभाषित नहीं किया जा सकता, इसकी परिभाषा अलग–अलग देशों के लिए भिन्न–भिन्न हो सकती है। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी का जो खाका तैयार किया है, वह विकास के चार स्तंभों पर आधारित है ये चार स्तम्भ है–संस्थागत, फिजिकल, सोशल और इकनोमिक इफास्ट्रक्चर। स्मार्ट सिटी मिशन का मूलमंत्र है–उस शहर में रह–रहें लोगों को जीवन–यापन के लिए एक उपयुक्त गुणवत्तापूर्ण माहौल प्रदान करना। वहां के लोगों को स्वच्छ और स्थिर पर्यावरण, रोजगार, निवेश, क्वालिटी लाइफ के साथ–साथ उनकी समस्याओं का स्मार्टनेस के साथ समाधान देना भी है। इसके तहत जनसूचनाएँ और जनता से जुड़ी दिक्कतों का समाधान ऑनलाइन ही उपलब्ध होगा साथ ही इलेक्ट्रानिक सर्विस डिलीवरी की भी व्यवस्था होगी, जिससे यहां के लोगों को किसी भी सेवा का तुरन्त लाभ मिल सके। स्मार्ट सिटी में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाये जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन शहरों में रहने वाले लोग शहर की आँख और कान होंगे, ताकि किसी भी तरह के अपराध या जनता से जुड़ी समस्याओं का तुरन्त निपटारा किया जा सके। शहरों में अपराध को रोकने के लिए वीडियों क्राइम मॉनीटरिंग व्यवस्था होगी, इसके तहत क्राइम होने से पहले उसे रोका जा सके या अपराध होने की स्थिति में तुरन्त कार्यवाही की जा सके।

स्मार्ट सिटी के उद्देंश्यः–

वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, भारत की वर्तमान जनसंख्या की लगभग 31 प्रतिशत आबादी शहरों में बसती है और इनका सकल घरेलू उत्पाद में 63 फीसदी का योगदान है। ऐसी उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक भारत की आबादी का 40 फीसदी हिस्सा शहरों में रहेगा और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 75 प्रतिशत का होगा। तथा साल 2050 तक दुनिया की 75 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करेगी, जिससे यातायात व्यवस्था आपातकालीन सेवाओं और अन्य व्यवस्थाओं पर जबर्दस्त दबाव होगा। इसके लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है। ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं लोगों में निवेश को आकर्षित करने, विकास एवं प्रगति के एक बेहतर चक्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में एक कदम है।

स्मार्ट सिटी के निम्न उद्देश्य है–

- शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- परिवहन व्यवस्था को बेहतरीन बनाना।
- स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय संसाधनों, स्त्रोतों और बुनियादी संरचनाओं का सक्षम ढंग से विकास करना।
- शहर की छवि खराब करती झुग्गी झोपड़ियों को हटाना।
- झुग्गी में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक सुविधा मुहैया कराना।
- 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना।

स्मार्ट सिटी की विशेषताएँः–हर शहर की कुछ अपनी विशेषताएं होती है। कई शहर बनावट में ही जटिल और दुर्गम होते है, और कुछ शहर काफी सहज होते है। स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित होने वाले शहर अन्य शहरों से कई मामलों में अलग होंगे। स्मार्ट सिटी शब्द सुनते ही सबसे पहले जो तसवीर उभरती है वह कुछ ऐसी होती है–

- एक शहर जहां की जलवायु शुद्ध हो, लोग खुली हवा में सांस ले सकें।
- एनर्जी मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत इन शहरों में पावर सप्लाई 24 घन्टे रहेगी। इसके ऊर्जा के अन्य स्त्रोतों का इस्तेमाल किया जायेगा। बिजली की चोरी न हो सके इसके लिए पक्की व्यवस्था की जायेगी।
- सार्वजनिक यातायात उपलब्ध हो, जो विश्व स्तरीय हों।
- यहां रहने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी मिलेगा।
- दिन भर लोगों को ट्रेफिक में न जूझना पड़े, इस हेतु इंटेलिजेन्ट ट्रेफिक सिस्टम लगा होगा, जिसमें जाम और दुर्घटनाओं को कम करने की पूरी व्यवस्था होगी। इसके लिए शहर की ट्रेफिक में ऐसे कैमरे लगे होंगे जो संदिग्धों की पहचान होने पर तुरन्त सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को भेजेगी।
- इन शहरों में स्मार्ट पार्किग की व्यवस्था होगी, जिसमें स्वचालित कारे खुद अपने लिए पार्किग ढूढें।
- सड़के, कारें और इमारते हर चीज एक–एक नेटवर्क से जुड़ी हों, इमारतें अपने आप बिजली बन्द करें।
- शहर ऐसा जिसका कूड़ादान भी स्मार्ट हो, और सफाई की उचित व्यवस्था होगी।
- गैस सिलेण्डर के लिए लाइन लगने के बजाय, पाइपलाइन घर तक आये।
- ऐसी व्यवस्था जिसमें अपराध कम हो और लोग चैन से रह सकें।
- शहर में बिजली के ग्रिड से लेकर सीवर पाइप सब कुछ अच्छे नेटवर्क में हो।
- स्कूल–कॉलेज, अस्पताल आदि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो।
- सस्ते घर खासकर गरीबों के लिए अर्थात् शहर ऐसा हो जहां लोगों के रहन–सहन में समानता दिखे।
- अनाधिकृत कालोनियों की सडांध मारती गलियां न हो। झुग्गी–बस्तियां न हों।
- उच्च क्वालिटी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगी।

- नागरिकों की सुरक्षा, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए हो।
- मजबूत आईटी–कनेक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन।
- गुड–गवर्नेंस, खासकर ई–गवर्नेंस और सिटीज पार्टिसिपेशसन।

वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के अन्तर्गत इन शहरों में स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट की सुविधा होगी। स्मार्ट मीटर्स के अलावा लीकेज से बर्बाद होने वाले पानी को बचाया जायेगा। इन शहरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर क्वालिटी मानीटरिग की भी व्यवस्था होगी। आज देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, वह है रोजाना घरों और फैक्टरियों से निकलने वाले लाखों टन कूड़े और कचरों का निपटारा। आज इन ठोस कचरों का निपटारा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लैडफिल साइट्स पर डंप किया जाता है। इस निर्मित सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के लिए प्लांट होंगे, साथ ही वेस्ट को कम्पोस्ट में भी तब्दील किया जायेगा, जिसका उपयोग खेती के लिए हो सकें। इन शहरों में गंदे पानी के ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था होगी, इसके कांस्ट्रक्शन से निकलने वाले वेस्ट को रिसायकल करने की सुविधा होगी।

निष्कर्षः–

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि व्यापक विकास, भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को एकीकृत करके ही होता है। सरकार की कई क्षेत्रीय योजनाएं इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए शामिल होती है, भले ही उनके रास्ते अलग है। शहरी योजनाओं के स्वरूप में बदलाव करके उन्हें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस शहर में तब्दील करने में अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन एक दूसरे के पूरक साबित होने वाले है। साथ ही बेटी बचाओं–बेटी पढ़ाओं, सुकन्या समृद्धि योजना, हृदय (विरासत शहर विकास एवं सम्बर्धन योजना) जन–धन योजना, मुद्रा योजना, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना, आदर्श ग्राम योजना, उन्नत भारत अभियान, सार्क सैटेलाइट अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इण्या, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय तथा पर्यटन मंत्रालय की तीर्थस्थल कायाकल्पन एवं आध्यात्मिकता संवर्द्धन अभियान योजनाद्ध भारत को शीर्ष प्रदान करने के लिए कार्यशील है। निःसन्देह सरकार की इन योजनाओं के पूर्ण क्रियान्वयन के उपरान्त भारत, वैश्विक परिदृश्य के शीर्ष फलक पर अग्रसर होगा।

REFERENCES

[1]. K Gopal: Smart India will be ushered in sooner than we believe is possible. Construction Opportunities, p. 30 - 31
[2]. Y Z Khan : Smart City "A Dream to be true. International Journal of Linguistics and Computational Applications (IJLCA), volume 2, issue 1, p. 1 - 5
[3]. Ryser, Sustainable, Healthy, Liveable, Creative Cities, Or Just Planning Cities? Proceedings REAL CORP, p. 447 - 456
[4]. Report of the Ministry of Urban Development, Govt. of India "On Smart City Mission (2015)"
[5]. Census of India (2011): Provisional Population Totals, Paper-2, Vol .1 Rural-Urban Distribution, India
[6]. Pathak, C.R. (2010): Urbanization in India and the Management of the Mega Cities (unpublished)
[7]. Pathak, C.R. (2004): Towards an Urbanization Policy in India, Journal of Institute of Town Planners, NewDelhi, July- September
[8]. Sivaramakrishnan, K.C. 2011, Re-visioning Indian cities, The urban renewal mission. New Delhi: Sage.
[9]. C. Chandramouli and R. General, "Census of india 2011, Provisional Population Totals. New Delhi: Government of India, 2011.
[10]. P. Neirotti, A. De Marco, A. C. Cagliano, G. Mangano, and F. Scorrano, Current trends in smart city initiatives: Some stylised facts, Cities, vol. 38, pp. 25–36, 2014.
[11]. L. G. Anthopoulos, "Understanding the smart city domain: A literature review," in Transforming city governments for successful smart cities. Springer, 2015, pp. 9–21.